

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग”
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 222]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 सितम्बर 2002—भाद्र 18, शक 1924

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2002

प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक 6035/18/2002.—राज्य शासन, सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड बरार की अधिसूचना क्रमांक 1129-734-एस-टी 26 जून, 1948 द्वारा मध्य नगरपालिका परिषद् रायगढ़ के स्थान पर रायगढ़ नगर के वृहत्तर नगरीय क्षेत्र का स्वरूप ग्रहण करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अधीन नगरपालिक निगम, रायगढ़ के गठन का आशय करता है. साथ ही नगरपालिक निगम, रायगढ़ गठन होने की तिथि से छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 328 (1) के अधीन नगरपालिका परिषद् रायगढ़ को भंग करने का आशय रखता है.

कोई भी व्यक्ति या संस्था या स्थानीय निकाय की उपरोक्त आशय के विषय में कोई भी आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा. आपत्तियों पर विचारोपरांत राज्य शासन, नगरपालिक निगम, रायगढ़ के गठन के विषय में अंतिम निर्णय लेगा.

Raipur, the 7th September 2002

PRELIMINARY NOTIFICATION

No. 6035/18/2002.—In exercise of the powers conferred under Section 7 of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby expresses its intent to constitute a Municipal Corporation in place of Municipal Council, Raigarh, constituted *vide* notification No. 1129-734-S-T, 26th June 1948 of Central Provinces & Berar, as it has transformed into a larger urban area. The State Government also intends to dissolve the Municipal Council, Raigarh under section 328 (1) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 in the event of formation of Municipal Corporation, Raigarh.

Any person or institution or local body having any objection with the above intention, may submit their objection within 30 days from the date of this publication in the official Gazette. After considering all such objections, the State Government shall take the final decision.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विवेक ढोंड, सचिव.